www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 308 || लखनऊ
बुधवार
11 फ़रवरी 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:46
सूर्यास्तः 05:56
अधिकतमः 27°00
न्यूनतमः 12°00

पेज 03

विशेष समाचार
जनकपुरी हादसे से इंसानियत ... >> पेज 02
सहारा की जमीन पर विधानसभा ... >>पेज 04
अरिजीत सिंह ने संन्यास की घोषणा के ...

सीएम योगी बोले जो कानून तोड़ेगा उसे जहन्नुम मिलेगा, कायदे से रहना सीख लो

'कयामत तक बाबरी के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा'

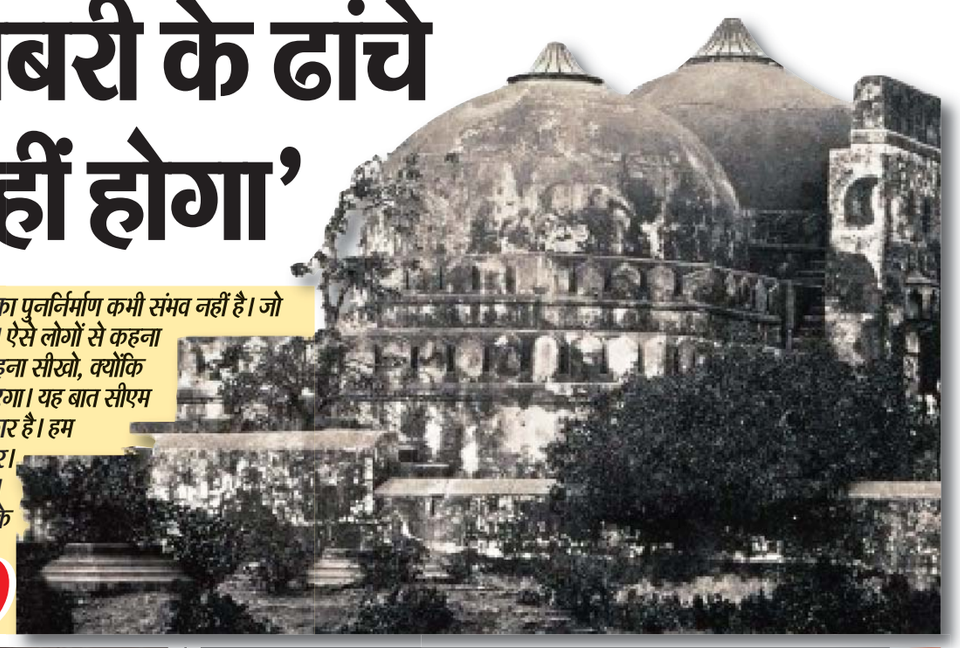

"योगी बोले कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं, वे ऐसे ही सड़-गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कानून तोड़ेगा, वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। यह बात सीएम योगी ने मंगलवार को बाराबंकी में कही। उन्होंने कहा- ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया न मंदिर। कोई संदेह है। राम को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होगी। उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ना। रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं। जो राममक्तों पर गोली चला रहे थे, अब इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। राम सबके हैं, इसमें भेद नहीं। कुछ अवसरवादी राम को भूल जाते हैं।"

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। योगी बाराबंकी में श्री हनुमत विराट महायज्ञ एवं श्रीरामार्चा पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यज्ञ मंडप में आहुति दी। इस दौरान संत बलराम दास ने मखाने और लावा की माला पहनाकर योगी का स्वागत किया। इसके बाद योगी ने कहा- हम सब भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था। पहले गरीबों की जमीन पर कब्जा हो जाता था। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई। हमारी सरकार में सब सुरक्षित हैं। योगी ने कहा- बेटी सुरक्षित होगी, तो समाज अपने आप सुरक्षा का एहसास करेगा। व्यापारी सुरक्षित होगा, तो तरक्की होगी। पहले वेतन देने का पैसा नहीं होता था। आज सभी को वेतन समय पर मिल रहा। सरकार करोड़ों लोगों को पेंशन दे रही है। आज प्रदेश तरक्की कर रहा है। कहा- सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जो कानून अपने हाथ में लेगा, तो कानून उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। पहले की सरकारों में शौचालय नहीं थे। लोगों को मुंह बंद करके खेतों में जाना पड़ता था। आज हर घर में शौचालय है। अब बहन-बेटियों को बाहर नहीं पड़ता। बेटियों के जन्म से लेकर शादी का खर्च भी सरकार कर रही है।

>> (शेष पेज 04 पर)

सीएम योगी के मंच पर पहुंचते ही लोग भारत माता के जयकारे लगाने लगे।

बाराबंकी से गुजरेगा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग

योगी ने कहा- 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बाराबंकी से होकर गुजरेगा, जिससे जिले के विकास को नई गति मिलेगी। बाराबंकी को SCR में शामिल किया गया है। इससे यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्यमंत्री सतीश शर्मा और प्रभारी मंत्री सुरेश राही के प्रस्ताव पर रामसनेहीघाट में भव्य औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा।

500 साल में मंदिर नहीं बना

सीएम ने कहा- 500 साल में कई राजा-महाराजा आए। 1947 में देश आजाद हुआ। सरकारें बनती रहीं। लेकिन, किसी मन में ये बात नहीं आई कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। मंदिर भाजपा की सरकार में बना। आज वहां लाखों भक्त दर्शन करने जा रहे।

हिंदूवादी संगठन ने मस्जिद ढहाने का ऐलान किया था

मस्जिद बनने का ऐलान होने पर यूपी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इसको ढहाने का ऐलान किया था। संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा था कि यूपी से कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद जाएंगे। वहां बन रही मस्जिद को ढहाने का काम करेंगे। 8 फरवरी को इस ऐलान से जुड़े होर्डिंग्स भी लखनऊ समेत कई जगहों पर लगाए गए थे। वहीं, लखनऊ में 15 गाड़ियां लेकर जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया।

मोदीजी आए तो गरीबों को घर मिले

योगी ने कहा- पहले गरीबों के घर नहीं बन पाए। मोदीजी आए, तो यूपी के 60 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले। पहले गांवों में बिजली नहीं थी, सड़कों पर गंदगी थी। अब घर-घर शौचालय बन गए। साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। पहले बिजली नहीं मिलती थी। कुछ चुनिंदा जिलों को ही बिजली मिलती थी। अब सभी 75 जिलों को बिजली मिल रही।

पेंगुइन का दावा : नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई

पूर्व सेना प्रमुख ने पब्लिकेशन की पोस्ट शेयर की, राहुल बोले- कंपनी झूठ बोल रही या नरवणे

अप्रकाशित

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी (Four Stars of Destiny)' पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया। कंपनी ने कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई कॉपी आई है।

>> (शेष पेज 04 पर)

इसके जवाब में राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा- या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं, या पेंगुइन कंपनी। वहीं कंपनी के बयान को पूर्व आर्मी चीफ ने एक्स पर रीपोस्ट किया। उन्होंने लिखा- यह है बुक पर स्थिति।

कांग्रेस का दावा- कंपनी ने दवाब में पोस्ट डिलीट किया

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने X पर लिखा कि पेंगुइन इंडिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, जाहिर है वे भारी दबाव में हैं। पेंगुइन ने जो उचित समझा वो किय, लेकिन चीफ अभी भी सच्चाई के साथ खड़े हैं। यह किताब 2024 में प्रकाशित हुई थी और अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध थी। पवन खेड़ा ने आर्मी चीफ नरवणे का एक पोस्ट भी शेयर किया है।

मोदी का प्लेन असम में हाईवे पर उतर सकता है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो यह पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा जब किसी पीएम का प्लेन पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर लैंड करेगा। यह एयरस्ट्रिप नेशनल हाईवे (NH) 127 के डिब्रूगढ़-मोरान हिस्से पर बनाई गई है। पीएम की मौजूदगी में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान एक स्पेशल एरियल डेमो करेंगे। इसमें विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेकऑफ दिखाएंगे। डेमो करीब 30-40 मिनट का होगा। असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी फाइटर एयरक्राफ्ट में मोरन हाईवे पर उतरेंगे। मुख्य सचिव रवि कोटा ने कहा कि 14 फरवरी को प्रधानमंत्री 4.4 km के एयरस्ट्रिप के उद्घाटन के लिए मोरन आएंगे। यह कार्यक्रम भारत की आपदा तैयारी, पूर्वोत्तर विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को दर्शाएगा।

मणिपुर के उखरुल में पांच दिन के लिए इंटरनेट बंद

उपद्रवियों ने 25 घर और चार सरकारी क्वार्टर फूंके

- लितान में घरों में लगी आग के धुएं आसमान में दूर से दिख रहे थे।
- उपद्रवियों ने करीब 25 घरों को आग के हवाले कर दिया।
- इंफाल से 35 किलोमीटर दूर लितान सरेइखोंग गांव में आगजनी की घटना हुई है।

तमसा संकेत, एजेंसी

इंफाल। मणिपुर में नई सरकार बनने के एक हफ्ते के भीतर ही हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने उखरुल जिले के लितान सरेइखोंग गांव में 25 घर और चार सरकारी क्वार्टर में आग लगा दी। हिंसा के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। 10 फरवरी की सुबह 11:30 बजे से अगले पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तांगखुल और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्स मौजूद हैं। हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी की शाम लितान सरेइखोंग में हुए एक शराब के नशे में झगड़े से हुई थी।

>> (शेष पेज 04 पर)

फास्ट न्यूज

बीजेपी के लिए ओवैसी ही इकलौते भगवान : रेवंत रेड्डी

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाजपा भगवान राम का नाम तो लेती है, लेकिन असल में उनके लिए सबसे बड़ा सहारा और इकलौता भगवान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए बार-बार ओवैसी को मुद्दा बनाती है। अगर भाजपा के राजनीतिक इतिहास और बयानों का विश्लेषण करें, तो उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान असदुद्दीन ओवैसी हैं।

पप्पू यादव को बेल, लेकिन जेल में ही रहेंगे

पटना। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंगलवार को MP-MLA कोर्ट से 31 साल पुराने मामले में जमानत मिल गई। हालांकि, वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े मामलों में पप्पू यादव को अभी जमानत नहीं मिली है। इन मामलों में बुधवार को सुनवाई होगी। तब तक पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल में ही रहेंगे। सुनवाई के दौरान पप्पू यादव ने जज के सामने पटना पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अपनी बात रखते समय वे भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे। पप्पू यादव ने दावा किया कि बेऊर जेल के अंदर उन्हें किसी तरह का इंजेक्शन देकर जान से मारने की साजिश रची जा रही है।

अंडरवियर में छिपाकर लाया था 45 लाख का सोना

अहमदाबाद। कस्टम विभाग ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दुबई के एक शख्स को 96 लाख रुपए के सोने के साथ पकड़ा है। इस शख्स ने अपने अंडरवियर में 45 लाख का सोना छिपा रखा था। जांच के दौरान व्यक्ति के पास से 24 कैरेट शुद्धता की दो पूरी सोने की छड़ें और एक कटी हुई छड़ भी मिली। ये छड़े उनकी अपनी जेब में रखे पर्स में छिपा रखी थीं। जब्त किए गए 325 ग्राम सोने की अनुमानित बाजार कीमत करीब 52 लाख रुपए आंकी गई है।

टपोरी मंत्री ने मुझे सदन में गालियां दीं : सुनील सिंह

अशोक चौधरी के साथ तीखी बहस, विधान परिषद में हंगामा

चर्चा

तमसा संकेत, एजेंसी

पटना। लंच ब्रेक के बाद विधानसभा में पथ निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा हुई। राजद विधायक सुरेंद्र राम ने तेजस्वी यादव को नौकरी मैन ऑफ द बिहार की उपाधि दी। इधर, बिहार विधान परिषद में मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। कल हए विवाद पर राजद के MLC ने सवाल उठाए। जिसके बाद पक्ष-विपक्ष के MLC में बहस हुई। राजद MLC बेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे को देखते हुए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विपक्ष के MLC को पूरे दिन की कार्यवाही के लिए सदन से बाहर कर दिया। सभापति ने सदन में मार्शल को भी बुलाया, ताकि MLC को बाहर किया जा सके। इस दौरान अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच तीखी बहस हुई। अशोक चौधरी ने सुनील सिंह से कहा, 'तुम क्या हो।' वहीं सुनील सिंह ने बेल में आकर, 'अशोक चौधरी होश में आओ' के नारे लगाए। दोनों ओर से औकात दिखाने देने तक की बातें हुईं। सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को टपोरी कहा। उन्होंने कहा, 'टपोरी मंत्री ने मुझे गालियां दीं।

ओम बिरला का लोकसभा में ना जाने का फैसला, 9 मार्च को प्रस्ताव पर चर्चा होगी

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वह स्पीकर की चेयर संभालेंगे। एजेंसी के मुताबिक विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी को बजट सत्र के वर्तमान सेशन का आखिरी दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। इससे पहले बजट सत्र के 10वें दिन संसद दो बार स्थगित हुई। दोपहर 2 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू हो सकी। शशि थरूर ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की।

>> (शेष पेज 04 पर)

अखिलेश यादव बोले- नए लेबर कोड लेबर के ही पक्ष में नहीं है

अखिलेश यादव ने कहा कि इस डील और ढील के बाद रुपये का क्या हाल होगा सरकार बताए। यादव ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। ये लेबरकोड लाए जो लेबर के पक्ष में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना आवंटित बजट ही खर्च नहीं कर रही है। पीएम ने गोद लिए गांव को अनाथ छोड़ दिया। सरकार मेरे सवालों का जवाब दे। सभी क्षेत्र की रैंकिंग में हम काफी नीचे आ गए हैं। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा लेकिन गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का शेर जंग खा रहा है।

राहुल का यह बयान पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के उस क्लैरिफिकेशन के बाद आया, जिसमें कहा गया कि नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं। पेंगुइन कंपनी ने कहा- अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने संसद में कहा कि बीजेपी को तीन बार बंगाल में हार देखनी पड़ी है। चौथी बार भी देखेंगे। सरकार ने बंगाल को बेहद कम फंड दिया। हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एजेंसी से हमे परेशान कर रही है लेकिन हम इसका भी जवाब देंगे, आप फाइल सीज रहे हैं, बजट रोक रहे हैं लेकिन बंगाल आगे बढ़ेगा। बंगाल के लेबर को लेबर नहीं सस्पेक्ट की तरह देखा जा रहा है।

सुविधाएं : आर्टिकल 370 हटने से ऐसा नहीं हुआ, राज्य बजट में अमरनाथ मंदिर को 180 करोड़

अमरनाथ यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया : उमर अब्दुल्ला

तमसा संकेत, एजेंसी

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अमरनाथ यात्रा को हमेशा कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों को लिए सुविधाएं आर्टिकल 370 के हटने के बाद ही आसान नहीं हुई हैं। कश्मीरियों ने हमेशा तीर्थयात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर गुफा तक पहुंचाया है। कश्मीरियों के बिना यात्रा कब मुमकिन हुई है? मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम ने साल 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने तीर्थक्षेत्र के विकास के लिए 180 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा। अब्दुल्ला ने यह बात विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के दावे के जवाब में कही। शर्मा ने कहा था कि अमरनाथ यात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार का खास नियम अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद ही मुमकिन हुआ। इससे पहले, 2026-27 के लिए अपना बजट पेश करते हुए, अब्दुल्ला ने सदन को बताया था कि उनकी सरकार दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ मंदिर जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा और आराम पक्का करने के लिए कमिटेड है।

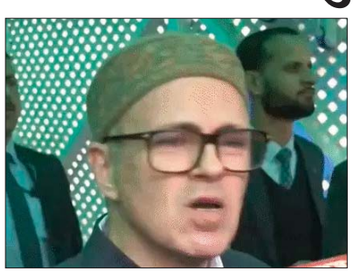

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया गया। इसमें अमरनाथ यात्रा के लिए भी एलान हुआ।

हर साल 3-5 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं अमरनाथ गुफा

अमरनाथ यात्रा आमतौर पर हर साल जून के अंत या जुलाई की शुरुआत से शुरू होकर अगस्त में रक्षाबंधन तक चलती है। ये लगभग 40-50 दिनों की अवधि होती है। इस दौरान हर साल 3 से 5 लाख से अधिक लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहलगाम और बालटाल के रास्तों से पहुंचते हैं। यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या चयनित बैंक शाखाओं के माध्यम से अग्रिम पंजीकरण अनिवार्य है।

असम में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश, 2.43 लाख नाम हटे

राज्य में अब 2.49 करोड़ वोटर, बंगाल में फाइनल लिस्ट की तारीख 14 दिन बढ़ी

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

गुवाहटी। चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को असम में हुए स्पेशल रिवीजन (SR) 2026 के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। EC के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में 2.43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अब राज्य में कुल 2,49,58,139 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 2,52,01,624 थी। स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के बाद लिस्ट में 2,43,485 नाम हटाए गए हैं। अब फाइनल लिस्ट में 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिलाएं और 343 थर्ड-जेंडर शामिल हैं। स्पेशल रिवीजन की इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 27 दिसंबर 2025 को पब्लिश हुई थी। इस पर 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां करने का समय था। 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में घर-घर (H2H) वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया था। असम की 126 विधानसभा सीटों पर अगले तीन महीनों में चुनाव होने हैं। इससे पहले 27 दिसंबर 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल जारी किया गया था। इसमें 10,56,291 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इनमें 93,021 हजार से ज्यादा D-वोटर यानी डाउटफुल वोटर शामिल नहीं किए गए थे। वोटर लिस्ट में से मौत, नई जगह शिफ्ट होने या डुप्लीकेट एंट्री होने की वजह से 10.56 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। D-वोटर वे लोग होते हैं, जिनकी नागरिकता पर सरकार को शक होता है। ऐसे लोगों को वोट देने की परमिशन नहीं होती। इन्हें फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत खास ट्रिब्यूनल तय किया जाता है और इन्हें वोटर कार्ड भी नहीं दिया जाता।

सम्पादकीय

राष्ट्रीय मिशन बने महाशक्ति बनना

कुछ समय पहले भारी मुनाफा कमाने वाली एक भारतीय कंपनी ने एक छोटी सी चीनी कंपनी से सौर ऊर्जा से जुड़ी तकनीक खरीदनी चाही, परंतु उसने देने से मना कर दिया। यह तब हुआ, जब भारत अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस का संस्थापक है। भारत ने फ्रांस के साथ इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 2015 में की थी। यह अपनी तरह का पहला बड़ा संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य 125 सदस्य देशों के साथ मिलकर 2030 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में एक ट्रिलियन डॉलर का निवेश और 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन है। चीन को कई बार इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया, पर उसने स्वीकार नहीं किया। विडंबना यह है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के अगुआ भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को चीन की छोटी सी कंपनी के पास ही सौर ऊर्जा से जुड़ी तकनीक मांगने जाना पड़ा। इसका कारण यह है कि हजारों करोड़ रुपये प्रति तिमाही का मुनाफा कमा रही भारतीय कंपनियां भी नई तकनीक के अनुसंधान में भारत में निवेश नहीं करना चाहती हैं। वे खुदरा माल-सेवाओं के आपूर्तिकर्ता मात्र के रूप में अपने व्यापार का विस्तार कर रही हैं और टेक्नोलाजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसी कमजोरी के चलते हम विश्व स्तर पर नेतृत्व देने में अक्षम हैं। विश्व शक्तियां हमें अक्षम ही बने रहने देना चाहती हैं। इसका ताजा उदाहरण अमेरिका के नेतृत्व वाला पैक्स सिलिका गठजोड़ है। पैक्स सिलिका महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में काम आने वाले दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति और प्रसंस्करण से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं को पिरोकर चीन जैसे देशों के इस क्षेत्र पर नियंत्रण से निकलने के उद्देश्य से बनाया गया है। पहले भारत ने इससे जुड़ने की इच्छा जताई थी, परंतु ट्रंप प्रशासन ने उसे नकार दिया था। इस पर भारत के कुछ उद्योगपतियों ने कहा था कि यदि सरकार उनके साथ सहयोग करे तो वे दुर्लभ खनिजों का खनन और प्रसंस्करण भारत में कर सकते हैं। भारत के पास चीन और ब्राजील के बाद दुर्लभ खनिजों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, जबकि अमेरिका इस मामले में विश्व में सातवें नंबर पर है। ट्रंप साम-दाम-दंड-भेद का प्रयोग कर ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रयास में इसलिए जुटे, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास विश्व का आठवां सबसे बड़ा दुर्लभ खनिजों का भंडार है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल भी कर ले तब भी 3.4 मीट्रिक टन के साथ उसका स्थान सातवां ही रहेगा। विचारणीय यह है कि दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में भारत को अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहिए या आत्मनिर्भर? जैसे ही भारतीय उद्योगपतियों ने स्वयं इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण करने की बात कही, अमेरिका ने तुरंत अपनी चाल बदलकर भारत को पैक्स सिलिका में जुड़ने के लिए आमंत्रित कर लिया। इसकी वकालत करने वाली एक लाबी के अनुसार इन दुर्लभ खनिजों का खनन और प्रसंस्करण बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए भारत का अमेरिका की अगुआई में काम करना आसान रहेगा, पर जब हमें यह सब आसानी से उपलब्ध होने लगेगा तो हम शिथिल पड़ जाएंगे और खनन और प्रसंस्करण तकनीकी में निवेश ही नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि इस जटिल काम को चीन ने कैसे कर लिया? चीन 1986 में ही अमेरिका को पीछे छोड़ दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। 1985-95 के बीच चीन में इन खनिजों का उत्पादन 464 प्रतिशत बढ़ा। 2004 आते-आते चीन विश्व भर के 90 प्रतिशत दुर्लभ खनिजों का निर्यातक बन चुका था। आज चीन विश्व दुर्लभ खनिजों का 70 प्रतिशत खनन, 90 प्रतिशत शोधन और रेयर अर्थ मैग्नेट के 90 प्रतिशत उत्पादन को नियंत्रित करता है। जो काम चीन 1980-90 के दशक में कर पाया वह हम आज क्यों नहीं कर सकते? आत्मनिर्भरता क्या आत्मसंदेह से आएगी। जब विश्व ने परमाणु तकनीक भारत को देने से मना कर दिया था तो क्या हमने परमाणु बम नहीं बना लिया था? इसके उलट उदाहरण भी देख लीजिए। म हमेशा फाइटर जेट विदेश से आयात करते रहे हैं। इसके चलते हम आज तक इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं, जबकि विश्व की हर महाशक्ति अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूरोपीय संघ, चीन अपने फाइटर जेट और उसके इंजन स्वयं बनाते हैं। खबरें हैं कि भारत को एक बार फिर लाखों करोड़ रुपये खर्च करके फ्रांस, रूस या अमेरिका में से किसी एक से फाइटर जेट आयात करने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के बस अब मात्र 29 स्क्वाड्रन ही बाकी रह गए हैं, जबकि होने कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए। यह स्थिति इसलिए है, क्योंकि तेजस का उत्पादन समय से नहीं हो पाया और स्वदेशी जेट इंजन बनाने का कार्यक्रम भी अधूरा ही रहा। 1989 में प्रारंभ किए गए कावेरी जेट इंजन कार्यक्रम में भारत ने 2008 तक मात्र 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया और फिर उसे असफल पाकर तेजस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। पिछले 40 साल में भारत ने कावेरी इंजन कार्यक्रम पर अधिकतम 5000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि चीन तीन लाख पचास हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। आज चीन के पास छठी पीढ़ी के स्वनिर्मित लड़ाकू विमान जे-20 के लिए अपना जेट इंजन तैयार है, जबकि हम चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विदेश से खरीदने के लिए तीन-चार लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। क्या कोई यह वादा कर सकता है कि हम अंतिम बार विदेशी लड़ाकू विमान खरीदने जा रहे हैं?

जनकपुरी हादसे से इंसानियत शर्मिंदा है

> “जलबोर्ड पर सवाल उठता है कि इतना बड़ा गड्ढा करने के बावजूद उसने वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं की थी। जब ऐसे काम किये जाते हैं तो काम पूरा होने तक बैरिकेडिंग की जाती है, उसे तभी हटाया जा सकता है, जब काम पूरा हो जाये। काम पूरा हो जाने के बाद ही आम लोगों के इस्तेमाल के लिए सड़क को खोला जा सकता है।

भारत में दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होना एक सामान्य खबर है। इसके लिए लोगों की लापरवाही ही ज्यादातर जिम्मेदार होती है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ अपनी लापरवाही के कारण ही मारे जाते हैं बल्कि सच्चाई यह है कि दूसरों की गलतियों के कारण मरने वालों की संख्या ज्यादा है। इन दुर्घटनाओं के लिए सरकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो 2024 में इसके कारण 1.80 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी । देखा जाए तो इस तरह हर रोज 485 लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। दुर्घटनाओं को कम करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है लेकिन लोगों की लापरवाही इसमें बाधा बन रही है। सवाल यह है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो क्या सरकारी व्यवस्था और आम जनता अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाती है । भारत में निर्माण कार्यों के लिए सड़क और उसके आसपास खुदाई की जाती है, जिनके गड्डो में गिरकर कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं । 16 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 150 में एक दर्दनाक हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी। घने कोहरे के कारण उनकी कार सड़क किनारे निर्माण कार्य हेतु खोदे गए बड़े गड्ढे में गिर गयी थी जो कि पानी से भरा हुआ था। निर्माण कंपनी ने वहां कोई साइन बोर्ड तक नहीं लगाया हुआ था और न ही ऐसी बैरिकेडिंग की गई थी कि जिससे वाहनचालकों को खतरे का पता चल जाये। संबंधित सरकारी विभागों ने भी अपनी जिम्मेदारी की पूरी तरह से अनदेखी की हुई थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि घटनास्थल पर पूरा सरकारी अमला होने के बावजूद युवराज की जान नहीं बचाई जा सकी। जिन कर्मचारियों को युवराज की जान बचानी थी, वो ठंडे पानी के डर से दूर बैठे तमाशा देखते रहे और युवराज मौत के मुंह में चले गए। इस घटना को हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, ऐसी ही एक घटना और सामने आ गयी है। 5 फरवरी को दिल्ली जलबोर्ड द्वारा सड़क पर खोदे गए गड्ढे में बाइक सवार एक युवक कमल ध्यानी की गिरकर मौत हो गई है । कमल एक निजी बैंक में सहायक प्रबंधक

के पद पर कार्यरत था जो कि शाम को अपने घर वापस जा रहा था। वो रोज उसी रास्ते से घर जाता था लेकिन उसे पता नहीं चला कि दिन में जलबोर्ड द्वारा सड़क में गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। सड़क पर बैरिकेडिंग की गई थी लेकिन उसके बीच इतना रास्ता छोड़ दिया गया था कि मोटर साईकिल निकल सकती थी। शॉर्टकट के चक्कर में कमल सड़क के बीच खोदे गए गड्ढे में गिर गए और उनकी बाइक उनके ऊपर गिर गई। कई घंटों तक कमल उस गड्ढे में पड़े मौत से लड़ते रहे लेकिन जीत नहीं पाए। अब इस दुर्घटना को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उससे न सिर्फ व्यवस्था की लापरवाही सामने आ रही है बल्कि संबंधित लोगों की असंवेदनशीलता भी प्रकट हो गई है। इस खुलासे से ऐसे लग रहा है कि लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है। एक व्यक्ति मर रहा था लेकिन लोग जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे थे। अगर कमल को समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान भी बचाई जा सकती थी। घटनास्थल के पास एक कैफ़े के सीसीटीवी फुटेज में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यह घटना रात को 12 बजे हुई थी. बाइक सवार कमल ध्यानी अपनी बाइक सहित गड्ढे में गिरे तो वहां से एक कार में एक परिवार गुजर रहा था। कार चालक विपिन ने अपनी कार तुरंत रोक दी और देखा कि एक गड्ढे में कमल बाइक के नीचे दबे हुए हैं और उनकी बाइक की लाइट जल रही थी। विपिन ने तुरंत कैफे के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी देशराज को कमल के गड्ढे में गिरने की जानकारी दी । सुरक्षाकर्मी देशराज ने वहां मौजूद दिल्ली जलबोर्ड के कर्मचारी योगेश को घटना की जानकारी दी। योगेश ने फोन करके इस घटना की जानकारी जलबोर्ड के ठेकेदार राजेश प्रजापति को दे दी। इसके बाद कार सवार विपिन घटनास्थल से अपने घर चले गए। योगेश अपनी झुग्गी में जाकर सो गया और सुरक्षाकर्मी देशराज कैफे में जाकर बैठ गया। सूचना मिलने के बाद ठेकेदार राजेश अपने घर से घटनास्थल पर आया और कमल को गड्ढे में गिरा हुआ देखा। राजेश ने कमल को गड्ढे से बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं की और न ही उसने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। वो कमल को गड्ढे में गिरा हुआ देखकर भी उसे छोड़कर अपने घर चला गया। वो गड्ढा 14 फीट गहरा और 20 फीट लंबा था, घायल कमल उसमें से खुद नहीं निकल सकते थे और न ही कोई अकेला आदमी उन्हें उस गड्ढे से बाहर निकाल सकता था। इन लोगों का एक आदमी को मरते हुए यूं छोड़कर चले जाना बेहद शर्मनाक घटना है। ऐसा लगता है कि किसी में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं थी। इनमें से सिर्फ कार चालक विपिन का चले जाना समझ आता है क्योंकि वो परिवार के साथ वहां ज्यादा देर तक रुककर क्या करते । दूसरी बात है कि उन्होंने संबंधित लोगों तक घटना की जानकारी पहुंचा दी थी। वैसे अच्छा होता कि विपिन घटना की जानकारी पुलिस को भी दे देते। अगर वो ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता. उन्होंने भी सारी जिम्मेदारी गार्ड और कर्मचारी पर डालकर वो जगह छोड़ दी। पहला सवाल उस गार्ड पर उठता है जो घटनास्थल के पास बैठा रहा । उसने कमल को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। घटनास्थल पर मौजूद होने पर उसकी पहली जिम्मेदारी थी, कि वो इस घटना की जानकारी पुलिस को देता। कमल के परिजनों ने कमल की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दे दी, इसलिए पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। गार्ड ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की, कि योगेश और राजेश ने पीड़ित को गड्ढे से बाहर निकालने का कोई इंतजाम किया है या नहीं । वो आराम से बैठा हुआ देखता रहा. जब घटनास्थल पर कोई हलचल नहीं हो रही थी तो उसे पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। योगेश और राजेश ने तो इंसानियत को बहुत शर्मिंदा कर दिया है क्योंकि वो तो सीधे इस घटना से जुड़े हुए थे। कितनी अजीब बात है कि एक आदमी गड्ढे में पड़ा मौत से लड़ रहा था और योगेश उसे बचाने की जगह आराम से झुग्गी में सो रहा था। राजेश देर रात को घटनास्थल पर पहुंच गया और कमल की हालत भी देख ली लेकिन कुछ करने की जगह घर जाकर सो गया। वो तो ठेकेदार था और घटना का उससे सीधा संबंध था लेकिन उसने भी पुलिस को नहीं बताया। हो सकता है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हों । इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि राजेश ने इसकी सूचना शायद अपने मुख्य ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों को दी हो। ये लोग अपनी लापरवाही की पोल खुलने के डर से सवेरे मामले को रफादफा करने की सोच रहे हों। कितनी अजीब बात है कि एक आदमी गड्ढे में तड़फ-तड़फ कर मर रहा था और ये लोग उसकी जान बचाने की जगह आराम से घर जाकर सो रहे थे।

राजेश कुमार पासी

इसलिए संक्रमणकालीन ...

कमलेश पांडेय

ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 के नीतिगत मायने बेहद अहम

ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 में रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने से सरकार और स्टेकहोल्डर्स दोनों को अल्पकालिक व दीर्घकालिक नुकसान हुआ है हालांकि सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम मानती है जबकि उद्योग जगत दीर्घकालिक हानि का दावा करता है। आंकड़े बताते हैं कि आम बजट 2026 और उससे ठीक पहले आए आर्थिक सर्वे भी केंद्र सरकार के बढ़ते वित्तीय घाटे की ओर इशारा कर चुके हैं, इसलिए बेहतर तो यह होता कि मोदी सरकार ऐसे द्विपक्षीय हानिप्रद फैसले लेने से पहले इससे जुड़े उद्योग जगत व अन्य स्टेक होल्डर्स से उन्मुक्त हृदय से बातचीत के बाद ही किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचती। जहां तक सरकार को नुकसान की बात है तो सरकार को सालाना 15,000-20,000 करोड़ जीएसटी (GST) राजस्व का सीधा नुकसान हुआ क्योंकि रियल मनी सेक्टर 86% राजस्व का स्रोत था। वहीं, इस क्षेत्र में सक्रिय 400+ कंपनियों के बंद होने से कॉर्पोरेट टैक्स और FDI (25,000 करोड़) प्रभावित हुए। जहां तक स्टेकहोल्डर्स को हानि की बात है तो रियल मनी गेम्स सेक्टर में 2 लाख नौकरियां (प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से) खतरे में हैं जिसमें डेवलपर्स, मार्केटर्स और फिनटेक शामिल हैं जिससे 50 करोड़ गेमर्स अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की ओर मुड़ सकते हैं जिससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ने के आसार प्रबल हैं। हालांकि, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिया है कि 45 करोड़ लोगों को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था जबकि नए प्रतिबंध से ई-स्पोर्ट्स ($1-2 बिलियन) मजबूत होगा। इस प्रकार लंबे समय में नया राजस्व (टूर्नामेंट्स, स्पॉन्सरशिप) नुकसान की भरपाई करेगा। बताया जाता है कि जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन)

अधिनियम, 2025 को अगस्त 2025 में संसद के दोनों सदनों से मात्र दो दिनों में पारित किया गया, वह त्वरित निर्णय है, जिसने 'रियल मनी गेम्स' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जो अर्थव्यवस्था पर कई दुष्प्रभाव डाल चुका है और आगे भी पड़ेगा। जहां तक नौकरियों पर प्रभाव की बात है तो इससे लगभग 2 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, क्योंकि 400 से अधिक कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। इंडस्ट्री बॉडीज के अनुसार, $25 अरब डॉलर के सेक्टर का बड़ा हिस्सा रियल मनी गेमिंग था, जिसका अचानक अंत होने से मानव संसाधन संकट पैदा हो गया। वहीं, जहां तक सरकारी राजस्व हानि की बात है तो सरकार को सालाना 20,000-25,000 करोड़ रुपये के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, जिसमें जीएसटी (GST) प्रमुख है। इससे डिजिटल इकोसिस्टम जैसे फिनटेक, विज्ञापन और कंटेंट क्रिएशन प्रभावित हुए हैं। दिलचस्प तो यह कि सरकार के तुगलकी फैसलों का असर भारत में होने वाले विदेशी निवेश पर भी पड़ेगा। इसलिए जहां तक निवेश प्रभाव की बात है तो देश में होने वाले 25,000 करोड़ के विदेशी निवेश (FDI) पर असर पड़ा है, क्योंकि नीतिगत अनिश्चितता से निवेशक पीछे हट रहे हैं। आखिर इसके त्वरित पारित होने से परामर्श की कमी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास कमजोर किया। वहीं, जहां तक अन्य जोखिम की बात है तो उपभोक्ता अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स या ग्रे मार्केट की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ सकता है। हालांकि ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन समग्र आर्थिक नुकसान प्रमुख चिंता है। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 पर सरकार ने उद्योग संगठनों को स्टेकहोल्डर मीटिंग्स, संसदीय बहस और आधिकारिक बयानों के माध्यम से आश्वासन दिए। जिसमें मुख्य फोकस रियल मनी गेमिंग प्रतिबंध के बावजूद स्किल-बेस्ड सेक्टर की सुरक्षा और विकास पर था। इसलिए संक्रमणकालीन समर्थन देते हुए सरकार ने 6-12 महीने का ट्रांजिशन पीरियड घोषित किया, जिसमें प्रभावित कंपनियों को लाइसेंस कन्वर्जन और रिस्किलिंग फंड की सुविधा दी गई। जहां तक कानूनी निपटारा की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि अधिनियम व्यवसाय स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता बल्कि जुआ रोककर स्वस्थ इकोसिस्टम बनाता है। इससे उद्योग का अधिकांश विरोध शांत हुआ। यही वजह है कि ई-स्पोर्ट्स उद्योग ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 पर मुख्य रूप से चिंता जताई, लेकिन पूर्ण विरोध कम था। दरअसल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन (EPWA) ने बिल पारित होने से ठीक पहले पीएम मोदी को पत्र लिखकर स्किल-बेस्ड गेम्स और चांस-बेस्ड गेम्स के बीच अंतर न करने पर आपत्ति दर्ज की। क्योंकि इनकी प्रमुख चिंताएं निम्नलिखित हैं- पहला, एसोसिएशन ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से खिलाड़ियों की आजीविका (कोचिंग, स्ट्रीमिंग, टूर्नामेंट आयोजन, कंटेंट क्रिएशन) खतरे में पड़ जाएगी।

माओवाद से ...

रामस्वरूप रावतसरे

बस्तर में अब राष्ट्रवाद के साथ जनजातीय संस्कृति के उत्सव की बयार

छत्तीसगढ़ का बस्तर कभी वामपंथी आतंकवाद के लिए कुख्यात रहा है। अब यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आवाज गूँज रही है और सुनने वालों में पूर्व नक्सली भी थे। 'बस्तर पंडुम' के जरिए माँ दंतेश्वरी की इस पुण्यभूमि की समृद्ध जनजातीय संस्कृति-विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने 7 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के सबसे बड़े उत्सव 'बस्तर पंडुम' का आज जगदलपुर में उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर के लोग जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं और यह महोत्सव दुनिया को बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक देता है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और अन्य मंत्री मौजूद रहे। 'बस्तर पंडुम' महोत्सव को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ आना, अपने घर आने जैसा लगता है। उन्होंने कहा, "बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि माँ दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है।" राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा, "इस वर्ष के पंडुम में पचास हजार से अधिक लोगों द्वारा जनजातीय संस्कृति तथा जीवन-शैली से जुड़े अनेक प्रदर्शन किए जाएँगे। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करती हूं।" राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान माओवाद से मुख्य धारा में लौट रहे बस्तर की सुंदरता की तारीफ की और कहा कि यहाँ विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। उन्होंने कहा, "माओवाद के कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान

यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई-बहनों को हुआ। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई के परिणामस्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है।" उन्होंने कहा, "बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार छोड़े हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे हैं, वो सामान्य जीवन जी सकें। उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार की 'नियद नेल्लानार योजना' ग्रामीणों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार के प्रयास और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बल पर आज बस्तर में विकास का नया सूर्यादय हो रहा है। गाँव-गाँव में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद विद्यालय फिर से खुल रहे हैं और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।" राष्ट्रपति ने नक्सलवाद छोड़ मुख्यधारा में लौटे लोगों से देश के संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने की अपील करते हुए कहा, "यह लोकतंत्र की ताकत ही है कि ओडिशा के एक छोटे से गाँव की यह बेटी, भारत की राष्ट्रपति के रूप में आपको संबोधित कर रही है।"

जरा हटके

इसके साथ ही ...

डॉ ब्रजेश कुमार मिश्र

बांग्लादेश का आम चुनाव : भारतीय विदेश नीति की परीक्षा

12 फ़रवरी 2026 को बांग्लादेश में होने वाला आम चुनाव साधारण अर्थों में सत्ता परिवर्तन का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह उस प्रश्न का उत्तर देगा कि 2024 के जनान्दोलन के बाद बांग्लादेश किस रास्ते पर चलेगालोकतान्त्रिक पुनर्निर्माण की ओर या फिर नई राजनीतिक अनिश्चितताओं और बाहरी प्रभावों की गिरफ्त में। वर्षों से जमी सत्ता-केन्द्रित राजनीति, संस्थाओं के क्षरण और बढ़ते सामाजिक असंतोष के बाद यह चुनाव बांग्लादेशी लोकतन्त्र की विश्वसनीयता की निर्णायक परीक्षा बन चुका है। इसके नतीजे केवल ढाका की सत्ता-राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बंगाल की खाड़ी की सामरिक दिशा, दक्षिण एशिया के शक्ति-सन्तुलन और भारत की सुरक्षा तथा कूटनीतिक प्राथमिकताओं को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के समकालीन राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनकर उभरा। बढ़ती महँगाई, बेरोज़गारी, शासन में केन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार और लोकतान्त्रिक संस्थाओं के क्षरण के विरुद्ध छात्रों और युवाओं के नेतृत्व में शुरू हुआ आन्दोलन कुछ ही दिनों में व्यापक जनान्दोलन में बदल गया। ढाका सहित कई प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिन पर नियन्त्रण के लिए सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया। जनहानि, गिरफ्तारियाँ और दमन के आरोपों ने सरकार की वैधता पर गम्भीर प्रश्न खड़े किए। लम्बे समय से सत्ता में रही आवामी लीग पर यह आरोप गहराता गया कि उसने लोकतन्त्र को औपचारिकता तक सीमित कर दिया है। अन्ततः सत्ता-संरचना चरमराई और देश एक नए राजनीतिक संक्रमण के दौर में प्रवेश कर गया। इस सत्ता-संक्रमण के बाद बांग्लादेश में एक अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक स्थिरता बहाल करना और देश को निष्पक्ष चुनाव की ओर ले जाना बताया गया। इस दौर में चुनावी सुधार, मतदाता सूची की शुद्धता, मीडिया की स्वतन्त्रता और न्यायिक संस्थाओं की भूमिका जैसे मुद्दे केन्द्रीय बहस बने रहे। चुनाव आयोग द्वारा 12 फ़रवरी 2026 की तिथि घोषित किए जाने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि यह चुनाव केवल सरकार चुनने का नहीं,

बल्कि 2024 के जनान्दोलन की राजनीतिक दिशा तय करने का माध्यम भी होगा। चुनावी परिदृश्य में इस समय एक जटिल और बहुस्तरीय प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। एक ओर पारम्परिक राजनीतिक दल अपने खोए हुए आधार को पुनः संगठित करने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर 2024 के आन्दोलन से निकली नई नागरिक और युवा राजनीतिक शक्तियाँ व्यवस्था-विरोधी एजेंडे के साथ सामने आई हैं। इसके साथ ही इस्लामिक और रूढ़िवादी दल भी सामाजिक नेटवर्क और धार्मिक पहचान के सहारे अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह त्रिकोणीय संघर्ष बांग्लादेश की राजनीति को पहले से कहीं अधिक अनिश्चित और संवेदनशील बना रहा है। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य के समानान्तर बांग्लादेश तेजी से अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और तुर्कीचारों देश अपने-अपने हितों के अनुरूप ढाका में राजनीतिक,आर्थिक औरसामरिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की दिलचस्पी विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी और हिन्द-प्रशान्त रणनीति से जुड़ी हुई है। सेन्ट मार्टिन द्वीप को लेकर होने वाली चर्चाएँ इसी सन्दर्भ में देखी जाती हैं, साथ ही अगस्त क्रान्ति के मूल में भी यह द्वीप रहा है। यद्यपि आधिकारिक रूप से किसी सैन्य अड्डे की योजना से इनकार किया जाता रहा है, फिर भी समुद्री मार्गों की निगरानी, नौवहन सुरक्षा और रणनीतिक उपस्थिति के लिहाज़ से यह क्षेत्र अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। चीन ने बांग्लादेश में अपने आर्थिक और सामरिक निवेश को लगातार विस्तार दिया है। बन्दरगाह विकास, ऊर्जा परियोजनाएँ, बुनियादी ढाँचा और रक्षा-सहयोग के माध्यम से चीन ने बांग्लादेश को अपने व्यापक क्षेत्रीय दृष्टिकोण का हिस्सा बना लिया है। बेल्ट एन्ड रोड पहल के तहत कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स पर जोर ने बांग्लादेश को चीन के लिए एक महतत्त्व-पूर्ण साझेदार बना दिया है। यह विस्तार केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि इसका स्पष्ट भू-राजनीतिक निहितार्थ भी है, जो भारत-चीन प्रतिस्पर्धा के सन्दर्भ में विशेष महत्व रखता है। पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ सम्बन्धों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश में जुटा है। रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और हथियार आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में सम्पर्क बढ़ाने के संकेत मिलते हैं। तुर्की, जो हाल के वर्षों में इस्लामिक देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, बांग्लादेश में सांस्कृतिक, धार्मिक और रक्षा-उद्योग के माध्यम से प्रभाव स्थापित करना चाहता है। इन दोनों देशों की सक्रियता भारत के लिए सामरिक चिंता का विषय है, विशेषकर तब जब क्षेत्रीय सन्तुलन पहले से ही सम्वेदनशील बना हुआ है। भारत और बांग्लादेश के सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गहरे रहे हैं, किन्तु बदलते राजनीतिक हालात ने इस रिश्ते को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि उसकी पूर्वी सीमा की सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता और बंगाल की खाड़ी में उसकी सामरिक उपस्थिति से सीधे जुड़ा हुआ है। सीमा-प्रबन्धन, अवैध तस्करी, उग्रवाद और 'चिकन नेक' कॉरिडोर जैसी सम्वेदनशील भौगोलिक संरचना भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहती है। आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाएँ और बन्दरगाह-उपयोग आपसी निर्भरता को दर्शाते हैं। इसके बावजूद जल-विवाद, विशेषकर तीस्ता नदी का मुद्दा, आज भी विश्वास-निर्माण की कसौटी बना हुआ है। राजनीतिक स्तर पर यह आवश्यक हो गया है कि ढाका और नई दिल्ली के बीच संवाद सन्तुलित और पारदर्शी रहे, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या भारत-विरोधी भावना को पनपने से रोका जा सके। 2026 के चुनाव के बाद बांग्लादेशजिस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसका सीधा प्रभाव भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय रणनीति पर पड़ेगा। भारत के लिए यह समय किसी एक राजनीतिक धड़े पर निर्भर रहने के बजाय व्यापक और समावेशी कूटनीति अपनाने का है। आर्थिक साझेदारी, जन-स्तरीय सम्पर्क, युवाओं और नागरिक समाज से सम्वाद तथा सुरक्षा सहयोग को संस्थागत ढाँचे में विकसित करना भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से अधिक लाभकारी होगा।

मैं चाहता हूँ कि युवा खिलाड़ी मेहनत और समर्पण से अपने सपने पूरे करें

सचिन ने अंडर-19 कप्तान आयुष को टेस्ट जर्सी भेंट की

नई दिल्ली, एजेंसी

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे जिम्बाब्वे से भारत लौटने के बाद सोमवार को सचिन तेंदुलकर से मिले। इससे पहले, मुंबई एयरपोर्ट पर कप्तान आयुष म्हात्रे समेत सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। म्हात्रे का पूरा परिवार उनके माता-पिता उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे। म्हात्रे भारत वापस लौटने के बाद सोमवार को महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के घर पहुंचे। आयुष म्हात्रे को सचिन तेंदुलकर से एक खास तोहफा मिला। तोहफा में सचिन ने अपनी टेस्ट जर्सी भेंट की,साथ ही उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ एक

संदेश भी दिया। वीडियो में सचिन ने म्हात्रे से कहा, यह वही जर्सी थी जिसे उन्होंने अपनी अंतिम टेस्ट सीरीज में पहना था। वो आगे कहते है, लगातार मेहनत करते रहो। ध्यान केंद्रित रखो। लोगों के बहकावे में मत आओ। अभ्यास करते रहो।

टूर्नामेंट में म्हात्रे ने शानदार कप्तानी की

टूर्नामेंट में म्हात्रे ने शानदार कप्तानी की, खासकर नॉकआउट मैचों में। फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 51 गेंदों में 53 रन बनाए और सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 59 गेंदों में 62 रन की पारी खेली। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 7 पारियों में कुल 214 रन बनाए और 30.57 की औसत से भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। इसके साथ ही टीम इंडिया रिकॉर्ड छठी बार टूर्नामेंट की चैंपियन बनी।

वैभव सूर्यवंशी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 439 रन बनाए। फाइनल में उन्होंने 175 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे।

म्हात्रे ने मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया

म्हात्रे ने मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। लिखा, मैं आपको स्क्रीन पर देखते हुए बड़ा हुआ। आज मैं आपके घर पर खड़ा हूं और आपकी यात्रा का एक हिस्सा अपने हाथों में थामे हुए हूं। इस सम्मान के लिए आपका धन्यवाद, सर। मैं इसे उसी आदर और सम्मान के साथ संभालकर रखूंगा, जैसे आपने सालों तक भारतीय क्रिकेट को सम्मान के साथ आगे बढ़ाया।

रोहित-कोहली ए प्लस से डिमोट होकर ग्रेड-बी पर खिसके

गिल, बुमराह और जडेजा को ग्रेड ए में जगह मिली, बीसीसीआई की रिटेंशन लिस्ट जारी

मुंबई, एजेंसी

BCCI ने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को ए प्लस ग्रेड से डिमोट करके बी ग्रेड में डाल दिया है। बोर्ड ने सोमवार को 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल प्लेयर्स की लिस्ट जारी की। ए प्लस ग्रेड को समाप्त कर दिया गया है। रोहित और कोहली के साथ बुमराह और जडेजा भी पिछले साल ए प्लस ग्रेड में शामिल थे। ताजा लिस्ट में इन दोनों को ग्रेड ए में शामिल रख गया है। वहीं, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ग्रेड ए में बरकरार रखे गए हैं। ग्रेड बी में टी-20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा 10 अन्य खिलाड़ियों को रखा गया है। ग्रेड सी में तिलक वर्मा और रिंकू सिंह समेत 17 खिलाड़ी हैं। बोर्ड ने रिटेन खिलाड़ियों को 3 ग्रेड में बांटा है। इनमें A, B और C शामिल हैं। बोर्ड ने अभी

रोहित और कोहली अब वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं। इसी वजह से उन्हें रिटेंशन लिस्ट में नुकसान हुआ है।

तक नए ग्रेड मॉडल की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं कहा है। कुछ दिन पहले इसे बदलने की बात कही जा रही थी। पिछले साल ए प्लेस ग्रेड में शामिल प्लेयर्स को 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे। वहीं, ग्रेड ए में 5 करोड़, ग्रेड बी में 3 करोड़ और ग्रेड सी में 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे। रोहित और कोहली अब केवल वनडे खेल रहे हैं। इस वजह से दोनों को ग्रेड बी में डाला गया है। दोनों दिग्गजों ने पिछले साल टी-20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। उसके बाद मई 2024 में टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था। विमेंस कैटेगरी में सिलेक्शन कमेटी ने 4-4 प्लेयर्स को ग्रेड ए और ग्रेड बी में जगह दी है। ग्रेड ए में कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रेड्रिग्ज और दीप्ति शर्मा शामिल हैं। जबकि ग्रेड बी में रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और स्नेह राणा के नाम हैं। महिलाओं के ग्रेड सी में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्लेयर्स को रखा गया है। इनमें क्रांति गौड़ और काश्वी गौतम जैसे नाम हैं। ए प्लस ग्रेड को समाप्त कर दिया है। इसमें शामिल बुमराह-जडेजा ग्रेड ए में रखे गए हैं। जबकि, गिल ग्रेड में बरकरार हैं। वे पिछले साल भी इसी ग्रेड में थे।

फास्ट न्यूज

'किसी भी फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं गोलमाल 5'

नई दिल्ली। फिल्म गोलमाल 5 लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं। कहा जा रहा है कि यह फिल्म दो और दो पांच से प्रेरित है। इसी बीच अब निर्देशक रोहित शेट्टी ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि गोलमाल 5 किसी भी क्लासिक बॉलीवुड फिल्म से प्रेरित नहीं है और इस तरह की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं।

यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे : ईरान

तेहरान। ईरान ने अमेरिका के दबाव को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि वो अपना यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम इनरिचमेंट) प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिलें या नए प्रतिबंध लगाए जाएं। रविवार को तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब कई सालों बाद ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत फिर से शुरू हुई है। ईरान चाहता है कि उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटें, जबकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक चाहता है।

ब्लूचिप फंड्स ने 1 साल में दिया 22% का रिटर्न

मुंबई। बीते कुछ महीनों में शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इससे कई निवेशकों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया है। हालांकि इसी बीच म्यूचुअल फंड की ब्लूचिप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स ने बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में लार्ज कैप ने 21% तक का रिटर्न दिया है। लंबे समय तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश करके आप इस फंड में आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं।

अरुणा ईरानी ने महमूद के साथ रिश्ते पर किया खुलासा

कहा- एहसानों के कारण उनके करीब आई, मेरा फायदा उठाया

मुंबई, एजेंसी

अरुणा ईरानी भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित एक्ट्रेसेस में से एक हैं। अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अरुणा प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने महमूद के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। हाल ही में जूम को दिए एक इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने फिल्मों में काम करने का मौका देने के लिए महमूद को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता एक तरह के एहसान और मजबूरी के भाव से बना था। उन्होंने कहा, महमूद जी ने मुझे सबसे पहले काम दिया। हमारा रिश्ता एक तरह के एहसान और मजबूरी के भाव से बना, और यही वजह थी कि यह हुआ। बाद में महमूद जी अपने अन्य प्रोजेक्ट्स में चले गए और मैं अलग शोज में बिजी हो गई। तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि वह मेरा खुले तौर पर फायदा उठा रहे थे। बॉम्बे टु गोवा और कारवां दोनों ही फिल्में हिट साबित हुईं। आमतौर पर ऐसी सफलता के बाद हर एक्ट्रेस का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अरुणा के साथ इसका उल्टा हुआ और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। इसकी वजह महमूद के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं थीं, जिसने उनके करियर पर बुरा असर डाला। दरअसल, बॉम्बे टू गोवा के दौरान अरुणा और महमूद के अफेयर की खबरें फैलने लगीं। यहां तक कहा गया कि दोनों ने चोरी-छिपे शादी कर ली है, जिसका असर अरुणा के फिल्मी करियर पर पड़ा और कई सालों तक उन्हें कोई काम नहीं मिला।

अरिजीत सिंह ने संन्यास की घोषणा के बाद पार्टी की

सिंगर ने स्टेज पर अनुष्का के साथ किया परफॉर्मेंस, आमिर खान से हुई खास मुलाकात

नई दिल्ली। हाल ही में सिंगर अरिजीत सिंह ने एक ऐसा एलान किया, जिसे सुनने के बाद करोड़ों फैंस का दिल टूट गया। दरअसल अरिजीत ने ये एलान किया कि वो सिंगिंग के करियर से संन्यास ले रहे हैं। सभी के मन में ये सवाल आया कि आखिरी अरिजीत को अचानक से हुआ क्या? इसके बाद कई तरह की खबरें आईं कि, अरिजीत सिंह पॉलिटिक्स ज्वॉइन कर रहे हैं। अब राजनीति का पता नहीं पर हां, फिलहाल हमें पार्टी का पता जो आजकल अरिजीत कर रहे हैं। सिंगर अरिजीत सिंह को हाल ही में पार्टी करते हुए देखा गया है। दरअसल हाल ही में अरिजीत को मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर के कॉन्सर्ट में देखा गया है। ये कॉन्सर्ट कोलकाता में चल रहा था, जहां अरिजीत सिंह दिखे हैं। अनुष्का शंकर के दोस्तों के साथ अरिजीत ने भी उन्हें ज्वॉइन किया और उनके साथ इस पार्टी में शामिल हुए। अनुष्का (Anoshka Shankar)

ने पार्टी के इनसाइड तस्वीरें और वीडियोज अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, अरिजीत खूब खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां अरिजीत अनुष्का से जैसे ही मिले तो उन्हें सीधा जाकर हग भी करते हैं। इसके साथ ही अरिजीत ने भी सोशल मीडिया पर ही अनुष्का का धन्यवाद भी किया है। इंस्टा स्टोरी में अरिजीत ने ये पोस्ट शेयर किया है। वैसे सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि इस कॉन्सर्ट में अरिजीत की सरप्राइज एंट्री तब और खास बन गई जब उन्होनें स्टेज पर जाकर अनुष्का शंकर के साथ परफॉर्म किया। खुद अरिजीत यहां अनुष्का के सितार की धुनों से अपनी आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध करते दिखे, जिसके वीडियोज अब वायरल हो रहे हैं।

रिटायरमेंट के बाद अरिजीत सिंह से मिले आमिर खान

दरअसल अरिजीत को आमिर मनाने गए थे ताकि वो बेटे जुनैद की फिल्म में गाना गा सकें। आमिर के बेटे जुनैद 'एक दिन' में दिखेंगे, जिसमें पांच गाने हैं और इन पाचों गानों को अरिजीत ने अपनी आवाज दी है। इसीलिए आमिर अरिजीत सिंह से मिलने पहुंचे थे। अरिजीत ने अपने करियर की शुरूआत एक छोटे से रियलिटी शो से की थी। इसके बाद उन्हें असली पहचान फिल्म 'मर्डर 2' के गाने 'फिर मोहब्बत करने चला है तू' से मिली थी। इसके बाद अरिजीत ने बैक-टू-बैक कई ब्लॉकबस्टर गाने गाए। अरिजीत ने अपने करियर में करीब 700 से ज्यादा गाने गाए हैं।

आपको बता दें कि 27 जनवरी को अरिजीत सिंह ने एलान किया था कि वो सिंगिंग करियर से संन्यास ले रहे हैं। हाल ही में आमिर खान ने भी बताया कि आखिर क्यों अरिजीत से मिले थे। जर्नलिस्ट सुभाष के. झा से खास बातचीत करते हुए आमिर खान ने अरिजीत सिंह से मिलने के लिए उनके घर जाने की वजह बताते हुए ये क्लियर किया कि उनका उद्देश्य सिंगर को वापसी के लिए मनाना नहीं था।

अमेरिका एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है, ताकि दुनिया के देश उनसे महंगी गैस खरीदें

भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का दबाव : सर्गेई लावरोव

मॉस्को, एजेंसी

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल न खरीदें। लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदें। उन्होंने यह बातें 9 फरवरी को डिप्लोमैटिक वर्कर्स डे के मौके पर कहीं। लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस की विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रम्प सरकार यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे, वे

अब भी जारी हैं। रूस के मुताबिक, यूक्रेन पर सहमति बनने के बाद भी अमेरिका नए प्रतिबंध लगाता रहा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका भारत और दूसरे BRICS देशों पर दबाव डाल रहा है कि वे रूस से दूरी बनाएं। रूस की तेल कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर रोक लगाई गई है और रूस के व्यापार और निवेश को सीमित करने की कोशिश हो रही है।

पश्चिमी देशों पर दूसरे देशों को उनका हक नहीं देने का आरोप

BRICS को लेकर लावरोव ने कहा कि इंडोनेशिया के जुड़ने से यह समूह और मजबूत हुआ है। रूस IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन चाहता है कि तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं को इन संस्थानों में उनका सही हक मिले। पश्चिमी देश इसका विरोध कर रहे हैं।

भारत जो मुद्दे उठाता है वे आज की जरूरतें

भारत की BRICS अध्यक्षता पर लावरोव ने कहा कि भारत जिन मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है, वे आज की जरूरतों से जुड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, खाने और ऊर्जा की सुरक्षा, तकनीक और AI जैसे विषय अहम हैं। उन्होंने बताया कि भारत फरवरी में AI पर एक बड़ी बैठक करने वाला है, जिसमें रूस भी शामिल होगा। रूस का कहना है कि AI को लेकर नियम ऐसे होने चाहिए, जिनमें हर देश की आजादी बनी रहे और कोई एक देश बाकी देशों पर हुक्म न चलाए। उन्होंने बताया कि इन हालात का असर रूस के दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर भी पड़ रहा है।

लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश अपनी पुरानी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते। ट्रम्प सरकार के आने के बाद यह और साफ हो गया है कि अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी दुनिया पर कंट्रोल चाहता है और अपने मुकाबले वालों को रोकने की कोशिश कर रहा है। रूस का कहना है कि उसकी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि यूक्रेन की जमीन से उसे कोई खतरा न हो और क्रीमिया, डोनबास और नोवोरोसिया में रहने वाले रूसी और रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है।

रूस में भारतीय छात्रों के शोषण के मामले बढ़े

2025 में दुनियाभर में 350 शिकायतें दर्ज, इनमें 200 रूस से

मॉस्को, एजेंसी

रूस की एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 7 फरवरी को हुई चाकूबारी की घटना में चार भारतीय छात्र घायल हो गए। इस घटना के बाद रूस में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और परेशानियों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसी बीच विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दुनिया भर में भारतीय छात्रों की तरफ से शोषण, उत्पीड़न और नस्लीय भेदभाव को लेकर की गई शिकायतों में से आधे से ज्यादा मामले सिर्फ रूस से जुड़े हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में 196 देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने ऐसी करीब 350 शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें से 200 से ज्यादा शिकायतें रूस में पढ़ने वाले छात्रों की थीं। पिछले तीन सालों में इन शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ी है। साल 2023 में 68

शिकायतें दर्ज हुई थीं। 2024 में यह संख्या बढ़कर 78 हो गई और 2025 में बढ़कर 201 तक पहुंच गई। रूस में पढ़ने वाले ज्यादातर भारतीय मेडिकल छात्र राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु से आते हैं। कम फीस और आसानी से एडमिशन मिलने की वजह से रूस लंबे समय से मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की पसंद रहा है। लेकिन अब वहां से लगातार शिकायतें सामने आने लगी हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

कार्यवाई : दिल्ली से टैक्सी में आए, बैग छोड़कर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में गए, लेकिन लौटे नहीं

जयपुर घूमने आए दो जापानी टूरिस्ट लापता

- पुलिस के अनुसार दोनों की तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है।
- टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि दोनों टूरिस्ट ने उससे जयपुर में अलग-अलग जगह घूमने का पूरा प्लान बताया था।

जयपुर, एजेंसी

जयपुर घूमने आए दो जापानी टूरिस्ट लापता हो गए। टैक्सी ड्राइवर को खाना खाने की कहकर दोनों मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। उनके बैग टैक्सी में ही थे। अशोक नगर पुलिस स्टेशन में ड्राइवर ने दोनों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार दोनों तीन दिन पहले ही इंडिया आए थे। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही

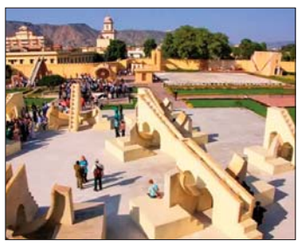

है। पुलिस का कहना है- आस-पास लगे CCTV फुटेज की जांच की है। फुटेज में दोनों टूरिस्ट रेस्टोरेंट में एंटर करने के करीब 5 मिनट बाद ही वहां से बाहर निकलकर पैदल जाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों टूरिस्ट फिलहाल कहां हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों टूरिस्ट को जयपुर में दो रात रुकना था। यहां से रणथंभौर और आगरा होते हुए दिल्ली लौटना था। उनके बैग टैक्सी में ही थे। काफी इंतजार के बाद भी पर्यटकों के नहीं पहुंचने पर अशोक नगर थाने में ड्राइवर ने रिपोर्ट दी। पुलिस ने दोनों टूरिस्ट के टैक्सी में रखे बैग अपनी

सुबह तक इंतजार करता रहा ड्राइवर

पर्यटकों के पास मोबाइल थे, लेकिन ड्राइवर के पास उनके नंबर नहीं थे। ड्राइवर 8 फरवरी की सुबह तक रेस्टोरेंट के बाहर उनके लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन दोनों वापस नहीं आए। उनके बैग टैक्सी में ही थे। काफी इंतजार के बाद भी पर्यटकों के नहीं पहुंचने पर अशोक नगर थाने में ड्राइवर ने रिपोर्ट दी। पुलिस ने दोनों टूरिस्ट के टैक्सी में रखे बैग अपनी कस्टडी में ले लिए हैं और मामले की जांच कर रही है। दोनों का जयपुर के अलग-अलग टूरिस्ट स्पॉट पर जाने का प्लान था।

6 फरवरी को दोनों दिल्ली पहुंचे थे

SHO (अशोक नगर) मोतीलाल ने बताया- टैक्सी ड्राइवर पिकेंद्र कुमार ने बताया- 6 फरवरी को दोनों जापानी पर्यटक (हिबिक्की शिब्बा और युमा) टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आए थे। अगले दिन वो दोनों को लेकर जयपुर के ब्रह्मपुरी स्थित एक होटल में आया था। वहां से रात को दोनों टूरिस्ट अशोक नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का कहकर गए थे। फिर वापस नहीं आए।

सेंसेक्स में 100 अंक की तेजी

मुंबई। शेयर बाजार में आज यानी 10 फरवरी को बढ़त है। सेंसेक्स करीब 100 अंक की तेजी के साथ 84,200 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 50 अंक की बढ़त है, ये 25,900 पर कारोबार कर रहा है। आज बैंकिंग, एनर्जी और ऑटो शेयर्स में बढ़त है। जापान का निक्केई इंडेक्स 2.54% चढ़कर 57,795 पर और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.18% ऊपर 5,307 पर कारोबार कर रहा है। हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग 0.49% चढ़कर 27,160 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 4,122 पर फ्लैट कारोबार कर रहा है। 9 फरवरी को अमेरिका का डाउ जोंस 0.04% ऊपर 50,135 पर बंद हुआ। नैस्डैक 0.90% और S&P 500 0.47% चढ़कर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों (FII) ने 9 फरवरी को 2,222 करोड़ और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 263 करोड़ के शेयर खरीदे। दिसंबर 2025 में FIIs ने कुल 34,350 करोड़ के शेयर्स बेचे थे। इस दौरान बाजार को संभाल रहे DIIs ने 79,620 करोड़ के शेयर खरीदे थे।

चांदी ₹3,759 बढ़ी, कीमत ₹2.57 लाख प्रति किलो

दो दिन में ₹12,495 महंगी, सोना ₹824 बढ़कर ₹1.56 लाख पर पहुंचा

नई दिल्ली, एजेंसी

चांदी-सोने के दाम में आज 10 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 10 फरवरी को एक किलो चांदी की कीमत 3,759 रुपए बढ़कर 2,57,424 रुपए किलो पर पहुंच गई है। सोमवार को इसका भाव 2,53,665 रुपए किलो था। इससे पहले शुक्रवार को चांदी की कीमत 2,44,929 रुपए किलो थी। वहीं, आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 824 रुपए बढ़कर 1,55,700 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को ये 1,54,876 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सर्राफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1,76,121 रुपए और चांदी ने 3,85,933 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। IBJA की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज,

ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता। इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। इस साल अब तक सोने की कीमत 22,505 रुपए बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपए का था, जो अब 1,55,700 रुपए हो गया है। वहीं, चांदी 27,004 रुपए महंगी हो गई है। 31 दिसंबर 2025 को एक किलो चांदी की कीमत 2,30,420 रुपए थी, जो अब 2,57,424 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में सोने-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई थी। इस दौरान सोना करीब 15% तक सस्ता हो गया था।अब कीमतें स्थिर होते ही निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी शुरू कर दी है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि अभी सोने-चांदी में एकमुश्त पैसा लगाने से बचना चाहिए। इसकी जगह धीरे-धीरे निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा। 2025 में सोना 57 हजार रुपए (75%) बढ़ा है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो 31 दिसंबर 2025 को 1,33,195 रुपए हो गया। चांदी इस दौरान 1.44 लाख रुपए (167%) बढ़ी।

एलडीए कंसल्टेंसी कंपनी से करवाएगा सर्वे, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

सहारा की जमीन पर विधानसभा भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू

66 नया विधानसभा भवन और सचिवालय परिसर न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लखनऊ के शहरी विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन का सही उपयोग और परियोजना का नियोजित विकास शहर की आधुनिक इमारतों और संरचनाओं के मॉडल के रूप में सामने आएगा। एलडीए और कंसल्टेंसी कंपनी की संयुक्त रिपोर्ट और विशेषज्ञ सलाह के बाद ही शासन अंतिम निर्णय लेगा। यह परियोजना लखनऊ के लिए ऐतिहासिक होने के साथ-साथ राज्य प्रशासन के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। सहारा शहर की विपुल खंड में स्थित 245 एकड़ जमीन पर नए विधानसभा भवन और सचिवालय परिसर के निर्माण की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस कार्य के लिए विशेषज्ञ कंसल्टेंसी कंपनी को नियुक्त किया है, जो जमीन का तकनीकी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी करेगी। अधिकारियों ने बताया कि कंसल्टेंसी कंपनी को दो महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही शासन यह निर्णय लेगा कि नया विधानसभा भवन और सचिवालय परिसर किस स्वरूप में विकसित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यह रिपोर्ट परियोजना की नींव

होगी और इसके आधार पर सभी विभागों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को परियोजना का नोडल विभाग बनाया गया है। वहीं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को विशेष कार्य इकाई बनाकर तकनीकी पहलुओं पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है।

भूमि का इतिहास और लीज रद्द होना

यह जमीन पहले नगर निगम और एलडीए के अधीन थी, जिसे बाद में सहारा इंडिया को लीज पर दिया गया था। हालांकि, जमीन का गलत इस्तेमाल और लीज शर्तों के उल्लंघन के कारण नगर निगम ने सहारा इंडिया की लीज रद्द कर दी। अब यह 245 एकड़ जमीन पूरी तरह से शासन के नियंत्रण में है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम नए विधानसभा भवन और सचिवालय परिसर के निर्माण की दिशा में पहली और महत्वपूर्ण कड़ी है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ लोकदल की आपात बैठक

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह की अगुवाई में मंगलवार को 8 माल एवेन्यू स्थित कार्यालय में किसान संगठनों के साथ एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में अमेरिका के दबाव में किए जा रहे तथाकथित भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को किसान विरोधी, संविधान विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दिया गया। किसान नेताओं ने एक स्वर में इस समझौते का विरोध करते हुए सरकार को कड़ी चेतावनी दी। बैठक में लोकदल के पदाधिकारियों और किसान संगठनों के वक्ताओं ने कहा कि यह समझौता देशहित में नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक मजबूरी का परिणाम है, जिसकी भारी कीमत भारतीय किसान चुका रहा है। नेताओं का आरोप है कि यह समझौता भारतीय कृषि को तबाह करने की एक सोची-समझी साजिश है। किसान नेताओं ने कहा कि अमेरिका में किसानों को हर साल 60 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपये तक की सरकारी सब्सिडी, आधुनिक तकनीक, सस्ती बिजली, सस्ता डीज़ल और पूरी सरकारी सुरक्षा मिलती है, जबकि भारत का किसान महंगे बीज, महंगी खाद, महंगे डीज़ल, कर्ज और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी के बिना खेती करने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में शून्य आयात शुल्क पर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में प्रवेश देना और भारतीय किसानों पर 18 से 28 प्रतिशत तक नियांत शुल्क थोपना प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सीधा आत्मसमर्पण बताया गया। लोकदल किसान संगठन ने साफ शब्दों में कहा कि यह समझौता किसान विरोधी, संविधान विरोधी और राष्ट्र विरोधी है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपात बैठक में देश के कई वरिष्ठ किसान नेता मौजूद रहे, जिनमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. एम. सिंह, भारतीय किसान यूनियन (अम्बावत) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अचलावत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल राजेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन (दसहरी) के मनीष यादव, लोकदल अध्यक्ष अखिलेश सिंह मुन्ना, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा, किसान नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हूण सहित सैकड़ों किसान शामिल हुए।

फास्ट न्यूज

बम स्क्वॉड ने सील किया गोदाम

लखनऊ। लखनऊ के इटौंजा कस्बे में एक गोदाम में भारी मात्रा में विस्फोटक होने की सूचना से सोमवार देर रात हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर मौजूद रही। गोदाम में विस्फोटक मिला। जांच के बाद गोदाम को सील कर दिया गया है।

लोधेश्वर जल चढ़ाने जा रहे दोस्तों का लखनऊ में एक्सीडेंट

लखनऊ। लखनऊ के अयोध्या रोड पर दो दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया। वे कानपुर से बाराबंकी लोधेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। घायल युवक का लोहिया संस्थान में इलाज चल रहा है। कानपुर के रामनगर निवासी 32 वर्षीय अमित कुमार पांडेय दोस्त आमोद बाजपेई के साथ बाराबंकी लोधेश्वर महादेव मंदिर जा रहे थे। भाई दीपक कुमार पांडे ने बताया कि अमित हर साल महादेव को दर्शन चढ़ाने जाता था। सोमवार शाम को अपने दोस्त के साथ निकाला था। इस दौरान देर रात पुलिस ने फोन कर सूचना दी कि अमित गंभीर रूप से घायल हो गया है। अयोध्या रोड जीएस लोन के सामने किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी।

संदिग्ध हालात में महिला की मौत

मोहनलालगंज। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के भदेसुवा गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 7:40 बजे उन्हें ग्राम रहीमनगर भदेसुआ में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी।

बीजेपी पर एस.पी. मतदाताओं के नाम कटने का आरोप

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को ज्ञापन सौंपकर कई जिलों में फार्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची में अनियमितता की शिकायत की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि भा0ज0पा0 कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में फार्म-7 जमा कर समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम और पी0डी0ए0 समुदाय के लोगों के नाम कटने की साजिश की जा रही है। विशेष रूप से फतेहपुर, सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र, आगरा, सम्भल, मिर्जापुर, बुलन्दशहर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और बाँदा के कई पोलिंग बूथों में फार्म-7 जमा किए गए। इन सभी बूथों में मतदाता सूची से नाम अवैध रूप से हटाने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप है। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ मामलों में एक ही आवेदक द्वारा कई फार्म-7 पर हस्ताक्षर कर दिए गए, जबकि वास्तविक मतदाता अपने पते पर स्थायी रूप से निवासरत हैं। फतेहपुर के उदाहरण में पोलिंग बूथ संख्या 57 पर दर्जनों समाजवादी समर्थक मतदाताओं के नाम काटने के प्रयास किए गए। सहारनपुर में 55 हजार से अधिक फार्म-7 जमा किए गए, बलिया, मिर्जापुर, आगरा, सम्भल और बुलंदशहर में भी इसी प्रकार के बड़े पैमाने पर फार्म-7 जमा होने की जानकारी दी गई। ज्ञापन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत एफआईआर दर्ज करने और सभी फार्म-7 को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है।

पल्लवी को बाल पकड़कर लखनऊ पुलिस ने गाड़ी में डाला

वॅउ रेगुलेशन के समर्थन में निकाला मार्च, विधानसभा कूच के दौरान झड़प

- पल्लवी पटेल के साथ पहुंची महिलाओं के हाथों में नारे लिखे पोस्टर और तख्तियां हैं।
- पल्लवी पटेल के साथ आरक्षित वर्ग के सैकड़ों लोग पैदल मार्च में शामिल हुए।
- रिजर्व पुलिस लाइन के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। यहां पर पल्लवी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वह बैरिकेडिंग तक पहुंच गईं।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में पुलिस और पल्लवी पटेल के बीच आज झड़प हो गई। पल्लवी UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में सैकड़ों लोगों के साथ पैदल मार्च निकाल रही थीं। उनके साथ सैकड़ों महिलाएं इस मार्च में शामिल थीं। महिलाओं संग वह IT चौराहे से निकलीं और यहां से विधानसभा तक जाना था। मार्च जब रिजर्व पुलिस लाइन के पास से गुजरने लगा तो पुलिस ने पल्लवी पटेल को रोक दिया। वहां बड़ी-बड़ी कंटीली बैरिकेडिंग की गई थी। पल्लवी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने रोका। इस दौरान पुलिस और पल्लवी के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। पुलिस काफी देर तक समझाती रही लेकिन पल्लवी वहां से हटने को तैयार नहीं हुईं। करीब 15 मिनट की मान-मनौव्वल के बाद पुलिस ने एक-एक सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान सबको गाड़ियों में बैठा दिया गया, लेकिन पल्लवी सड़क पर लेट गईं। उन्हें पुलिस की गाड़ी तक ले जाने में मशक्कत करनी पड़ी। वह गाड़ी तक तो किसी तरह पहुंचीं, लेकिन गाड़ी के गेट पर अड़ गईं। महिला पुलिसकर्मी ने उनको हाथ और पीठ के सहारे अंदर करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जा रही थीं। इसके बाद उनके बाल पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल दिया। पल्लवी का कहना है कि UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को टालना आरक्षित और वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है। पल्लवी पटेल अपना दल (कमेरावादी) अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इनका सपा के साथ गठबंधन है। पल्लवी कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं।

अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला

अमेरिका से डील को बताया खेती-किसानी के लिए नुकसानदेह

तमसा संकेत, संवाददाता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा भेदभाव की राजनीति करती है और न्याय दिलाने में भी पक्षपात करती है। मंगलवार को संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से देश के किसानों और खेती-किसानी का भविष्य गंभीर खतरे में है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हर चीज विदेश से आएगी तो देश का किसान क्या उगाएगा और अपनी फसल किसे बेचेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसान को उसकी उपज की सही कीमत मिल पाएगी। उन्होंने अमेरिका के साथ हुई डील को खेती और किसानी के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि इससे देश का बाजार धीरे-धीरे विदेशियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पहले तीन काले कृषि कानून लेकर आई, जिससे किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा। अब नई नीतियों के जरिए देश की खेती और बाजार को विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों के खिलाफ रही है और उसकी नीतियां किसान को कमजोर करने वाली हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब किसान की आमदनी घटेगी तो वह घर कैसे चलाएगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएगा, बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाएगा और बेटियों को सम्मान के साथ विदा कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि आज के खाने और कल की बचत तक का सवाल भाजपा की नीतियों ने खड़ा कर दिया है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सोच बिचौलियों वाली है, जो उत्पादन की बजाय कमीशनखोरी से लाभ कमाना चाहती है।

हिंदूवादी संगठन का भगवा झंडा-फावड़ा लेकर मुर्शिदाबाद कूच

बोले- बाबरी मस्जिद की एक ईंट नहीं रखने देंगे, कब्र खोदेंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

कार्यकर्ता हाथ में भगवा झंडा और फावड़ा लेकर पहुंचे हैं।

लखनऊ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने संगठन के विशाल खंड-2, गोमती नगर स्थित कार्यालय पर उन्हें रोक लिया। संगठन पदाधिकारियों ने उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। इसके पहले पदाधिकारी-कार्यकर्ता 15 कार के काफिले के साथ कार्यालय पर जुटे। हाथ में भगवा झंडा, कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा- हम बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। जब एक बार बाबरी मस्जिद का नाम मिट चुका है तो फिर क्यों उसे जिंदा करके पूरे भारत का माहौल खराब किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद की एक भी ईंट नहीं रखने देंगे। जरूरत पड़ी तो मुर्शिदाबाद में कब्र खोदने का काम करेंगे। दरअसल, पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने की बात की है। संगठन इसका विरोध कर रहा है।

भगवा झंडा और फावड़ा लेकर पहुंचे कार्यकर्ता

विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारियों ने बताया की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से लगभग 15,000 सदस्य और पदाधिकारी पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुके हैं। सभी लोगों के हाथों में भगवा झंडा, फावड़ा और कुल्हाड़ी है। संदेश बिल्कुल साफ है कि बाबरी के नाम पर पश्चिम बंगाल समेत पूरे भारत में एक भी ईंट नहीं रखने देंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के संगठन मंत्री हिमांशु ने कहा कि हम लोग हाथों में फावड़ा, कुल्हाड़ी और भगवा झंडा लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने जा रहे हैं। सैकड़ों मस्जिद बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वारदात : पति-पत्नी, 3 बच्चे, रसोई की दीवार समेत 3 जगह सुसाइड नोट मिले, मौत की 2 थ्योरी

परिवार के 5 लोगों की लाश मिली

तमसा संकेत, एजेंसी

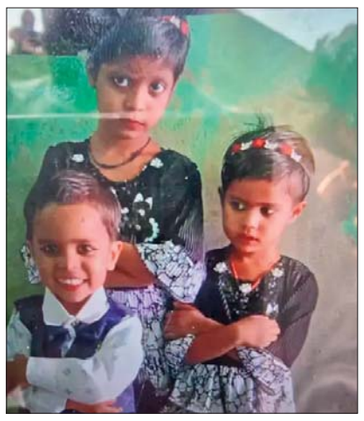

मथुरा। मथुरा में एक ही कमरे से एक परिवार के पांच लोगों की लाशें मिली हैं। मृतकों में पति, पत्नी और तीन बच्चे शामिल हैं। कमरे में बेड पर मां, एक बेटी और एक बेटा मिले, जबकि दूसरी बेटी चारपाई पर पड़ी थी। पति का शव फर्श पर मिला। पुलिस की दो थ्योरी सामने आई हैं। पहली- पति, पत्नी और बच्चों ने दूध में जहर मिलाकर आत्महत्या की। दूसरी- पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बच्चों की जान ली और बाद में खुद करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। SSP श्लोक कुमार ने बताया कि घटना का पता उस समय चला, जब सुबह बच्चे दिखाई नहीं दिए। इस पर पास में रहने वाले मनीष के भाई मौके पर पहुंचे। वे मेन गेट फांदकर अंदर गए और कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर सभी मृत पड़े मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को तीन सुसाइड नोट मिले हैं। पहला रसोई की दीवार पर लिखा था, जिसमें कहा गया कि मैं मनीष और सीमा अपनी मर्जी से मरे हैं और पुलिस किसी को परेशान न करे। दूसरा नोट कागज पर मिला, जिसमें भी यही बातें लिखी थीं। इसके अलावा, सुसाइड से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मनीष ने दुखों से परेशान होकर जान देने की बात कही है। पुलिस तंत्र-मंत्र के एंगल पर भी जांच कर रही है। इसी सिलसिले में उस मंदिर के पुजारी को हिरासत में लिया गया है, जहां मनीष अक्सर पूजा करने जाते थे। मनीष खेती करते थे। हाल ही में उन्होंने 19 लाख रुपए का प्लॉट बेचा था, जिसमें से 12 लाख रुपए खाते में आ चुके थे। घटना महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव की है। जिस कमरे में लाशें मिलीं, वह 10×15 फीट का है। इसी कमरे में रसोई भी बनी हुई है, जहां बर्तन रखे हुए हैं। रसोई के ऊपर की दीवार पर सुसाइड नोट लिखा मिला है। एक कागज भी पड़ा मिला, जिसमें सुसाइड नोट लिखा हुआ है कमरे में एक चारपाई और एक बेड रखा हुआ है। चारपाई पर हनी (5) मिली, जबकि बेड पर बेटा प्रतीक (2), बेटी प्रियांशी (4) और उनकी मां सीमा (32) थीं। मनीष (35) जमीन पर पड़ा मिला। पति के हाथ जले हुए मिले हैं, जबकि महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। फर्श पर एक मूसल और एक रस्सी मिली है। मूसल पर खून लगा हुआ था। इसके अलावा एक गिलास भी मिला है, जिसमें दूध के निशान थे।

पत्नी घर की इकलौती बेटी थी

मनीष की शादी हाथरस के मढ़नई गांव में हुई थी। पत्नी अपने मायके की इकलौती बेटी थी। ससुर के पास तीन बीघा खेती है, जो मनीष को ही मिलती थी। मनीष के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। उनके दो भाई सुधीर और जयकिशन हैं, जो घर के बगल में ही रहते हैं।

पृष्ठ 01 का शेष...

'कयामत तक ...

ये समाज की जिम्मेदारी है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा- यह रुकने और गिरने वाली सरकार नहीं है। 2017 से पहले यूपी की स्थिति बेहद खराब थी। हर चौथे दिन शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ता था। त्योहार शांति से नहीं मनाए जा सकते थे। गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, अराजकता चरम पर थी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश से अराजकता समाप्त हो चुकी है। विकास की नई गति दिखाई दे रही। माघ मेले में अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। किसान आज सुरक्षित माहौल में खेती कर रहा है। उसकी फसल सोना उगल रही है। सीएम ने बाराबंकी को विकास प्राधिकरण देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में बाराबंकी और अयोध्या सहित गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती और बहराइच से आए संत-महंत, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन के दौरान 79 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी हुआ, जिन्हें मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद दिया। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में TMC विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर, 2025 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी थी। इस दौरान नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लगे थे। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोग ईंट लेकर शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि, TMC ने 4 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। पूरा विवाद नवंबर- 2024 में शुरू हुआ था। तब TMC विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की छोटी प्रतिकृति बनाने की बात कही थी। जब बाबरी नाम के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया, तब उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए भावनात्मक मुद्दा है।

पेंगुइन का दावा ...

और न ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। यह कार्रवाई अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर मिली जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें दावा किया गया था कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी सर्कुलेट हो रही है। राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा के बाहर कहा- एमएम नरवणे ने X पर पोस्ट किया है, 'हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब अवेलेबल है। लिंक फॉलो करें। हैप्पी रीडिंग'। या तो एमएम नरवणे झूठ बोल रहे हैं, या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मैंने आर्मी चीफ पर विश्वास करना चुना। उन्होंने आगे कहा कि क्या आप एमएम नरवणे के बजाय पेंगुइन पर विश्वास करेंगे? किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार के लिए असुविधाजनक हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने X पर एक पोस्ट में पब्लिश्ड बुक और प्री-ऑर्डर कॉपी के बीच का अंतर बताया। पब्लिशर ने पोस्ट में लिखा कि बुक की प्लानिंग हो चुकी है लेकिन अभी ये बिक्री के उपलब्ध नहीं है। बीते 24 घंटे में पब्लिकेशन की तरफ से ये दूसरा पोस्ट है। पुलिस के मुताबिक इस किताब के पब्लिकेशन के लिए अभी संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी टाइटल वाली किताब की PDF कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध थी। आशंका जताई गई है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो कॉपी तैयार की थी, यह वही हो सकती है। इसके अलावा, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर किताब के कवर को इस तरह दिखाया गया, जैसे वह खरीद के लिए उपलब्ध हो।

मणिपुर के ...

जिसमें तांगखुल नागा समुदाय के स्टर्लिंग नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी। उखरुल जिले के लितान इलाके के आसपास गांवों में उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान राइफल से गोलियां भी चलाई गईं। इलाके में दहशत फैलने के बाद कर्फ्यू लागू किया गया। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन भारी सुरक्षा तैनाती के चलते काफी हद तक कंट्रोल में है। तनाव बढ़ने की आशंका के बीच लोगों ने बिना किसी प्रशासनिक मदद के अपने स्तर पर ही घर छोड़ना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि लितान थाना पुलिस ने लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की और कानून-व्यवस्था बनाए रखी है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है, जबकि अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेजे गए हैं। इंफाल से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित लितान एक छोटा व्यावसायिक कस्बा है, जहां तांगखुल नागा और कुकी दोनों समुदाय रहते हैं। यह आसपास के गांवों के लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करता है। सुरक्षा और समन्वय के लिए लितान पुलिस स्टेशन में जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया गया है।

लोकसभा स्पीकर...

कंपनी की सफाई इसलिए आई, क्योंकि बुक की अनऑथॉराइज्ड कॉपियों के लीक और ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। दरअसल, राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब लेकर लोकसभा पहुंचे थे। पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि उन्हें सदन में बोलने दिया जाए। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी बोले- आम आदमी को तीन टैक्स देने पड़ रहे हैं। एक इनकम टैक्स, दूसरा जीएसटी और तीसरा है महंगाई। जहां योजनाएं नहीं पहुंच पा रहीं वहां जीएसटी पहुंच जाती है। इसमें महंगाई सबसे गुपचुप तरीके से बढ़ रहा है लेकिन सरकार इसपर कुछ नहीं कर रही है।

सेक्स रैकेट में नहीं गई तो गर्लफ्रेंड की हत्या की

लाश थार में भरकर आगरा में फेंकी थी, एआई से पुलिस ने बनाया था चेहरा

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। यूपी के आगरा में सेक्स रैकेट में शामिल होने से मना करने पर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद किराये पर थार लेकर शव उसमें डाला और दिल्ली से करीब 250 किमी दूर आगरा लाया। फिर यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे शव फेंककर फरार हो गया। गर्लफ्रेंड की लाश 6 फरवरी को मिली थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने AI की मदद से उसके चेहरे को री-डेवलप किया। इसके बाद शव की शिनाख्त महोबा की सोनाली (25) के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि वह अपने बॉयफ्रेंड सनी (28) के साथ दिल्ली में लिवइन में रहती थी। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को सनी को हिरासत में लिया। पहले उसने बताया कि सोनाली ने फंदे से लटककर आत्महत्या की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। कड़ाई से पूछताछ करने पर सनी ने कबूल किया कि उसी ने सोनाली का गला दबाकर हत्या की। उसने बताया कि उसकी मां और सौतेले पिता ने भी उसका साथ दिया। वह सोनाली को सेक्स रैकेट में धकेलना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे डर था कि कहीं सोनाली उसके बारे में लोगों और पुलिस को न बता दे, इसी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार ने बताया कि सनी ने पूछताछ में बताया कि वह मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676